

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,  
गोण्डा।

सेवा में,

मा० कन्सलटेंट जुडिशियल,  
राष्ट्रीय हरित अधिकरण,  
नई दिल्ली।

संख्या: 3134/ खनन अनुभाग/2024,

दिनांक: 19 अप्रैल, 2024

विषय: ओ०ए०नं०-462/2023 राजाराम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में  
मा० एन०जी०टी० नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 व  
02.04.2024 के अनुपालन में कृत कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने  
के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.04.2024 व 21.12.2023 में दिये गये आदेश का संज्ञान लेने की कृपा करें। जिसमें मा० अधिकरण द्वारा अधोहस्ताक्षरी को जनपद गोण्डा में अवैध रूप से भण्डारित साधारण बालू को जब्त कर नीलामी कराते हुए नीलामी की धनराशि उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पक्ष में जमा करने के लिए निर्देशित किया गया था तथा उक्त आदेश के अनुपालन में कृत कार्यवाही की आख्या मा० अधिकरण के सम्मक्ष उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था।

इस सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि ओ०ए०नं०-462/2023 राजाराम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 21.12.2023 के अनुपालन में भण्डारित साधारण बालू के नीलामी हेतु निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ से मार्ग दर्शन माँगा गया था जो अभी अप्राप्त है, परन्तु निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उ०प्र० लखनऊ द्वारा ओ० ए०नं०-462/2023 राजाराम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश 07.11.2023 व 21.12.2023 के सन्दर्भ में श्रीमती रचना गुप्ता एडवोकेट, ऑन रिकार्ड/स्थायी अधिवक्ता उत्तर प्रदेश, मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली से विधिक राय प्राप्त की गई। श्रीमती रचना गुप्ता द्वारा दिनांक 26.02.2024 को विशेष सचिव/निदेशक भूतत्व व खनिकर्म विभाग उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय की विधिक राय उपलब्ध करायी कि आदेश दिनांकित 07.11.2023 के पैरा 9 व आदेश दिनांकित 21.12.2023 के पैरा 11 के सन्दर्भ में मा० उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका योजित की जाय।

विभाग की ओर से, खान अधिकारी गोण्डा, को पैरवी के लिए अधिकृत करते हुए मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में विशेष अनुमति याचिका योजित किये जाने हेतु सुश्री रचना गुप्ता एडवोकेट ऑन रिकार्ड एवं उनके सहयोगार्थ श्री आरोही भल्ला वरिष्ठ अधिवक्ता मा०

*Alu.*

उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित कर यथाप्रकिया विशेष अनुज्ञा याचिका योजित कराये जाने के निर्देश दिये गये थे।

तत्कम में ओ०ए० नं०-462/2023 राजाराम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 व 21.12.2023 के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में डायरी सं०-14576/2024 पर दिनांक 01.04.2024 को योजित कर दी गयी है। उक्त विशेष अनुमति याचिका में मा० अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांकित 07.11.2023 के प्रस्तर 9 को तथा आदेश दिनांकित 21.12.2023 के प्रस्तर (पैरा) 11 को आक्षेपित किया गया है तथा आदेश दिनांकित 07.11.2023 व 21.12.2023 के अनुपालन में जनपद गोण्डा में ग्राम-परसापुर व नवाबगंज गिर्द में अवैध रूप से भण्डारित साधारण बालू को जब्त किया जा चुका है तथा स्थानीय थाना नवाबगंज गोण्डा की देखरेख व सुपुर्दगी में है।

वर्तमान में सामान्य लोकसभा निर्वाचन 2024 की आधिकारिक घोषणा भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली द्वारा दिनांक 16.03.2024 को की गई है तथा अधिसूचना निर्गत होने के साथ ही आदर्श चुनावी आचार संहिता प्रभावी हो गई है, जिसके कारण अधोहस्ताक्षरी की ओर से निर्वाचन आयोग को सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत कराते हुए आदर्श चुनावी आचार संहिता के प्रभावी रहते हुए मा० अधिकरण के आदेश दिनांकित 21.12.2023 व 02.04.2024 के दृष्टिगत जनपद गोण्डा में ग्राम-परसापुर व नवाबगंज गिर्द में अवैध रूप से भण्डारित साधारण बालू की नीलामी हेतु अनुमति की मांग की गई है। अनुमति प्रदान होते ही आदर्श चुनावी आचार संहिता के मध्य ही नीलामी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जायेगी।

अतः आख्या एवं सूचना सादर प्रेषित है :-

संलग्नक:-यथोपरि।

भवदीय

(नेहा शर्मा)

जिला मजिस्ट्रेट,  
गोण्डा।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित :-

1. निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ।
2. सदस्य सचिव, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6) उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या।

जिला मजिस्ट्रेट,  
गोण्डा।

अ.प.

**RACHNA GUPTA**

Advocate-on-Record  
Standing counsel for State of U.P. in  
Supreme Court of India

**Office:** 228, M.C. Setalvad  
Block, Supreme Court,  
New Delhi-110001  
Ph: 011-23070950 – 23384711  
Mb.9811945301  
Email: [rachnagupta228@gmail.com](mailto:rachnagupta228@gmail.com)

February 26, 2024

To,  
Special Secretary/Director  
Geology and Mining Department,  
Uttar Pradesh Shasan, Lucknow, U.P.

Sub: Opinion relating for Original Application No.462 of 2023 titled as Raja Ram Singh Vs. State of U.P. & Ors. pending before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi viz. the orders dated 07.11.2023 & 21.12.2023 passed by the NGT, New Delhi.

Sir,  
I have gone through the relevant papers seeking my opinion by your goodself regarding filing of Appeal u/s 22 of the National Green Tribunal, Act, 2010 against the order dated 07.11.2023 & 21.12.2023 passed by the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi in Original Application No.462 of 2023 titled as Raja Ram Singh Vs. State of U.P. in the Hon'ble Supreme Court.

The facts briefly stated are:-

- (1) An Original Application No.462 of 2023 was registered on a letter petition received by post by the National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (NGT) wherein it was alleged by one Raja Ram Singh of Jai Mata Saryu Sankshna Samiti that illegal mining was being carried out by Brij Bhushan Sharan Singh Member Parliament from Kesarganj in Villgae Majharath, Jaitpur, Mewabganj, Tehsil Tarbganj, District Gonda and 700 overloaded trucks were transporting the extracted minor minerals and illegal sale of minor minerals.
- (2) Vide order dated 02.08.2023 the Tribunal constituted a Joint Committee comprising of Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), Central Pollution Control Board (CPCB), National Mission for Clean Ganga (NMCG), Uttar Pradesh Pollution Control (UPPCB) and District Magistrate Gonda to look into the grievances of the applicant Raja Ram Singh.
- (3) In compliance Joint Committee gave its report vide email dated 30<sup>th</sup> October, 2023 wherein it was noted that the mining Department Gonda has allotted the Mining Lease to Shri Satya Narayan S/o Shri Ram Avtar for removal of sand.

**RACHNA GUPTA**

Advocate-on-Record  
Standing counsel for State of U.P. in  
Supreme Court of India

**Office:** 228, M.C. Setalvad  
Block, Supreme Court,  
New Delhi-110001  
Ph: 011-23070950 - 23384711  
Mb.9811945301  
Email: [rachnagupta228@gmail.com](mailto:rachnagupta228@gmail.com)

- (4) It is submitted that the sand for which permit has been given to the said Satya Narayan was a short term permit for sand removal from Agricultural land with validity period of 03 months from 13.03.2023 to 12.06.2023.
- (5) Under the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concessions) Rules, 2021 Rule 52 provides that the Bhumidar of agricultural land may apply for grant of mining permit for removal of sand or morrum or Bajri or Boulder or any of these in mixed state. In the present case mineral involved is only Sand. The said rules provides that the District Officer shall cause an enquiry through Revenue and Geology and Mining Department regarding the title of the land and availability of minor mineral on the applied area. In the light of the report submitted by the concerned officer the District Officer may grant mining permit for a period not exceeding three months.
- (6) Under the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 issued by the Ministry of Environment Forest & Climate Change (MoEFCC), it considered under the heading "Management of Sand Deposited after flood on Agricultural Field of Farmers" that the flood management, compensation and status of ownership, loss of crops destroyed by floods and right to disposal of the sand left in the fields of the farmers. A committee was constituted under the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation to work in close coordination with the Ministry of Mines and Environment Forest and Climate Change to frame Regulations/Guidelines.
- (7) The Committee observed that due to flooding the agricultural land of farmers is destroyed and rendered infertile the farmer loses his livelihood as the produce of his land is destroyed by flood and becomes unsalable. The farmer is also deprived of the right of lifting sand from his land. He is therefore left helpless and destitute and leave their land in search of job. The committee further observed that "mining operations" means any operation undertaken for the purpose of winning any mineral. Accordingly, if desilting is undertaken perse with the objective of winning a mineral then only it will be construed as a mining operation. Apparently, if the desilting is undertaken not for winning an mineral, it will not be construed as mining operation and therefore, the farmer can remove the sand from his land without requiring the requisite permits. However, the Committee strongly feels that the farmer be given the right to use and dispose-off the sand accumulated over their land post flood, by incorporating the necessary provisions in the Mines and Mineral (Development and Regulation) Act, 1957"

**RACHNA GUPTA**

Advocate-on-Record  
 Standing counsel for State of U.P. in  
 Supreme Court of India

**Office:** 228, M.C. Setalvad  
 Block, Supreme Court,  
 New Delhi-110001  
 Ph: 011-23070950 – 23384711  
 Mb.9811945301  
 Email: rachnagupta228@gmail.com

- (8) It further provided under the Heading "Mining of sand" that removal of sand from the agricultural field by the owner farmer of the land from environment point of view will not be considered as mining operation and its removal and disposal can be allowed without the requirement of environment clearance till it is done only to the extent of reclaiming the agricultural land. The sand deposited after flood only be removed, so no mining/digging below the ground level is allowed. For removing sand in case where private land has gone into the river due to erosion, the requirement of mining lease and environment clearance will continue. This operation of removal of sand deposited on agricultural field should be done after a mapping of deposition is done by the Land Management Committee of the Gram Panchayat. The sand so deposited post flood can be removed by the farmer owning the land/group of farmers affected by this post flood sand deposition or the Gram Panchayat. Customary rights to remove and dispose off the sand should be given to the farmer affected by deposition of sand on account of sudden flood in his agricultural land.
- (9) Under the heading "Exemption of Certain Cases from being considered as mining for the purpose of requirement of environmental clearance" it was stated under clause 3 that removal of sand deposit on agricultural field after flood by farmers does not require prior environmental clearance.
- (10) Accordingly the Ministry of Environment Forest and Climate Change issued a notification on 15.01.2016 providing in Appendix-IX Exemption of certain cases from requirement of Environmental Clearance under clause 3 removal of sand on agricultural field after flood by farmer does not require environmental clearance. The clause 3 which is as under:-

"3. Removal of sand deposits on agricultural field after flood by farmers.

- (11) In view of the above guidelines and notification the Uttar Pradesh framed the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concessions) Rules, 2021. Under Rule 52 the Rules provided for grant of mining permit on agricultural land. Rule 52 is reproduced below:-

**Rule 52 -Procedure for Grant of Mining Permit on Agricultural Land:**

- (1) Notwithstanding anything contained in rule 74, the bhumidhar of agricultural land may apply for grant of mining permit for removal of sand or morrum or Bajri or Boulder or any

**RACHNA GUPTA**

Advocate-on-Record  
 Standing counsel for State of U.P. in  
 Supreme Court of India

**Office:** 228, M.C. Setalvad  
 Block, Supreme Court,  
 New Delhi-110001  
 Ph: 011-23070950 - 23384711  
 Mb.9811945301  
 Email: [rachnagupta228@gmail.com](mailto:rachnagupta228@gmail.com)

of these in mixed state deposited on his land in Form MM-8, in triplicate to the District Officer, accompanied by a non refundable fee of Rs. 2,000/-(Rupees two thousand) Only, and two copies of a cadastral Survey map on which the area, applied for, is clearly marked. The District Officer shall cause an enquiry, if deemed necessary, through Revenue and Geology & Mining Departments regarding the title of the land and availability of minor mineral on the applied area.

(2) In the light of the report submitted by the concerned Officer, the District Officer, may grant the mining permit for a period not exceeding three months in favour of the bhumidhar, after realizing double the amount of royalty in advance.

(12) The Tribunal failed to consider the true legal position as stated above and erroneously has in its order dated 07.11.2023 passed direction in para 9 that "till the next date of hearing fixed no short term permit for mining of minor minerals (Sand, Morrums etc.) be granted in the State of Uttar Pradesh without EC and SEIAA and consent from UPPCB and without following sustainable sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020".

(13) In a subsequent order dated 21.12.2023 the NGT in para 11 relating to unauthorised storage directed District Magistrate Gonda to take over the sand unauthorisedly stored and disposed of the same by way of open auction and deposit the amount thereby released with UPPCB without shall be entitled to utilize the said amount for restoration of environment in the area. In the said order it was directed in para 13 that the Director, Mining and Geology, State of U.P. is also directed to issue instructions that in cases where illegal mined material is found to have been stored un-authorizedly then the possession of the illegally mined material shall also be taken over and the same shall be disposed of by way of open auction and the amount realized shall be deposited with UPPCB which may utilize the same in the area affected by such illegal mining for restoration of environment.

(14) The above order dated 21.12.2023 is violative of the Uttar Pradesh Minerals (Prevention of Illegal Mining, Transportation and Storage) Rules, 2018, Rule 13 which provides imposition of penalty in case of illegal mining and also of letter dated 03.12.2018 issue by Principal Secretary, U.P. Government to all District Magistrate of Uttar Pradesh providing the manner in which the seized minerals are to be disposed of. The letter dated 03.12.2018 provides in case where the residual mineral available in the storage area is 10,000 cubic meters or more than it will be disposed of through e-tender. In cases where the

**RACHNA GUPTA**

Advocate-on-Record  
Standing counsel for State of U.P. In  
Supreme Court of India

Office: 228, M.C. Setalvad  
Block, Supreme Court,  
New Delhi-110001  
Ph: 011-23070950 - 23384711  
Mb.9811945301  
Email: [rachoagupta228@gmail.com](mailto:rachoagupta228@gmail.com)

residual minerals is less than 10,000/- cubic meter than the mineral should be dispose of by auction and the amount received is to be deposited in the royalty head of the Treasury.

- (15) The direction of the NGT to deposit the amount realized by auction to U.P. Pollution Control Board is totally in contravention of the letter dated 03.12.2018 which provides for the District Magistrate to auction the mineral and deposit the amount received by auction in the royalty head of the treasury. Apart from the fact it is violation of the Rules and practice followed by the Department, it is also causes of loss to the Revenue of the State.

After going through the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016, notification dated 05.01.2016 of the Ministry of Environmental Forest & Climate Change and the Uttar Pradesh Minor Minerals (Concessions) Ruled, 2021 and the orders dated 07.11.2023 and 21.12.2023, I am of the opinion that an Appeal u/s 22 of the National Green Tribunal Act, 2010 should be filed against the order dated 07.11.2023 passed by the NGT in O.A.No.463 of 2023 in the Hon'ble Supreme Court. The State is further loosing revenue due to the passing of the stay order. The period of limitation provided for filing the appeal is 90 days from the date of communication of the award, decision or order of Tribunal. The order was communicated to the District Magistrate, Gonda on 20.11.2023. Therefore, the filing of the appeal is already time barred but we can file an application for condonation of delay. However, looking at the urgency of the matter, the State should take urgent steps in filing of the appeal.

Yours faithfully,

*Rachna Gupta*

[RACHNA GUPTA]  
Advocate-on-Record

1002

प्रेषक,

जिला मजिस्ट्रेट,  
गोण्डा।

सेवा में,

मा0 कन्सलटेंट जुडिशियल,  
एन0जी0टी0,  
नई दिल्ली।

संख्या: 3048/खनन अनुभाग/2024,

दिनांक: 20 फरवरी, 2024

विषय: ओ0ए0 नं0-462/2023 राजाराम सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में  
मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-12-2023 के  
अनुपालन में कृत कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश  
दिनांक 21-12-2023 में दिये गये आदेश का संज्ञान लेने की कृपा करें।

अवगत कराना है कि उक्त मु0अ0सं0-529/2023 दिनांक 24-11-2023  
को खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा-21 एवं  
म0द0सं0 1860 की धारा-379 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करा दी गयी  
थी जिसकी विवेचना उप निरीक्षक, थाना नवाबगंज द्वारा की जा रही है। अन्तरिम  
विवेचना दिनांक 15-02-2024 में अवगत कराया गया है कि शिकायतकर्ता श्री राजाराम  
का कोई पता नहीं चल पा रहा है, साथ ही मा0एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक  
21-12-2023 के अनुपालन में बालू के नीलामी हेतु निदेशालय स्तर से मार्गदर्शन मॉंगा  
गया है, मार्गदर्शन प्राप्त होते ही नीलामी की कार्यवाही सम्पादित करायी जायेगी।  
संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

अपर जिला मजिस्ट्रेट  
गोण्डा।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित:-

- 1-निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन लखनऊ।
- 2-जिलाधिकारी गोण्डा।
- 3-पुलिस अधीक्षक गोण्डा।

4-सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।

5-मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-6) उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ।

6-क्षेत्रीय अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अयोध्या।

अपर जिला मजिस्ट्रेट  
गोण्डा।

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
गोण्डा।

सेवा मे,

निदेशक,  
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०,  
खनिज भवन, लखनऊ।

१२/१/२५

संख्या: ३०५६ / खनन अनु० / जॉच / २०२४

दिनांक: १७ फरवरी, २०२४

विषय:

ओ०ए०नम्बर-४६२/२०२३ राजाराम बनाम स्टेट उत्तर प्रदेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक २१-१२-२०२३ के पैरा-११, व १२ के सम्बन्ध में मार्ग दर्शन /अपील योजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक ओ०ए०नम्बर-४६२/२०२३ राजाराम बनाम स्टेट उत्तर प्रदेश व अन्य में मा० एन०जी०टी० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक २१-१२-२०२३ के पैरा ११ व १२ में आदेशित किया गया है जो निम्नवत है:-

" 11-The District Magistrate Gonda is directed to take over possession of the sand un-authorizedly stored and dispose of same by way of open auction and deposit the amount thereby realized with UPPCB which shall be entitled to utilize the above said amount for restoration of environment in the area.

12- Action taken report in this regard be also filed by the District Magistrate, Gonda on or before 15.02.2024 by email at judicial ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of image PDF

अतः मा० एन०जी०टी० न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक २१-१२-२०२३ के अनुपालन में उक्त भण्डारित साधारण बालू के निस्तारण से प्राप्त धनराशि को अलौह खनन विभाग के लेखाशीर्षक ०८५३ अथवा यू.पी.पी.सी.बी में जमा कराये जाने के संबंध में अथवा अपील योजित किये के सम्बन्ध में उचित मार्गदर्शन देने का कष्ट करें।  
संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,


( नेहा शर्मा )  
जिलाधिकारी,  
गोण्डा।

1004

कार्यालय जिलाधिकारी, गोण्डा।

(खनन अनुभाग)

पत्रांक: 3098/खनिज-डी0एम0एफ0/2023-24

दिनांक 21 मार्च, 2024

विषय: ओ0ए0 संख्या 462/2023 राजा राम सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 व 21.12.2023 तथा ओ0ए0 संख्या 481/2023 बलबीर सन्धु व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में दिनांक 04.08.2023 व दिनांक 09.02.2024 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय, विशेष अनुज्ञा याचिका (एस0एल0पी0) योजित किये जाने के सम्बन्ध में।

डॉ0 अभय रंजन,  
खान अधिकारी,  
गोण्डा।

कृपया उपरोक्त विषयक निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, लखनऊ के पत्र सं0- 2475/एम0-एन0जी0टी0 वाद/2023 दिनांक 14.03.2024 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके साथ शासकीय पत्र संख्या 1/511364/2024 दिनांक 04.03.2024 संलग्न अवगत कराया गया है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ0ए0 संख्या 462/2023 राजा राम सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2023 व 21.12.2023 तथा ओ0ए0 संख्या 481/2023 बलबीर सन्धु व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 04.08.2023 व दिनांक 09.02.2024 में पारित आदेश के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका (एस0एल0पी0) योजित किये जाने हेतु सुश्री रचना गुप्ता, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एवं उनके सहयोगार्थ श्री अरोही भल्ला, वरिष्ठ अधिवक्ता मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को आबद्ध किये जाने का आदेश निर्गत कर दिया गया है।

न्याय विभाग के आदेश के पृष्ठांकन में की गयी अपेक्षानुसार रुपये 4000/- की धनराशि बैंक ड्राफ्ट के द्वारा विधि व्यय हेतु सुश्री रचना गुप्ता एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के पक्ष में उक्त धनराशि का बैंक ड्राफ्ट जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास गोण्डा से तैयार कराकर सुश्री रचना गुप्ता एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित कर यथाप्रक्रिया ससमय विशेष अनुज्ञा याचिका योजित कराना सुनिश्चित करें।

  
जिलाधिकारी,  
गोण्डा।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन, लखनऊ।
3. श्री विवेक कुमार, खान निरीक्षक, गोण्डा को इस निर्देश के साथ कि कृपया सुश्री रचना गुप्ता एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क स्थापित कर विशेष अनुज्ञा याचिका तत्काल तैयार कराना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,  
गोण्डा।